



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, वीरवार, 8 अप्रैल, 2010/18 चैत्र, 1932

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अप्रैल, 2010

**संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-6/2010-लेज.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07-04-2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 4) को वर्ष 2010 के अधिनियम संख्यांक 9 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,  
**अवतार चन्द डोगरा,**  
सचिव (विधि)।

---

**हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2010**

---

**धाराओं का क्रम**

धाराएँ :

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार।
2. परिभाषाएं।
3. कर का भार।
4. मोटर यानों पर कर के उद्ग्रहण के विशेष उपबन्ध।
5. कतिपय परिस्थितियों में मोटर यानों पर कर की छूट।
6. धारा 3 के अधीन कर उद्गृहीत करने के सिद्धान्त।
7. सकल आवर्त से कटौतियां।
8. कतिपय मामलों में छूट (सैट-ऑफ)।
9. सबूत का भार।
10. रजिस्ट्रीकरण।
11. रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों द्वारा इस अभिव्यक्ति का बिल इत्यादि जारी किया जाना कि विक्रीत माल स्थानीय माल है।
12. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना।
13. प्रवेश कर का निर्धारण, वसूली इत्यादि।
14. आदेशों की अंतिमता।
15. नियम बनाने की शक्ति।
16. 2005 के अधिनियम संख्यांक 16 का निरसन।

**अनुसूचियां ।**

## हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 7 अप्रैल, 2010 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 है।

संक्षिप्त  
नाम और  
विस्तार।

(2) इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश के समस्त स्थानीय क्षेत्रों में होगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध परिभाषाएं न हो,-

(क) "स्थानीय क्षेत्र में माल लाना" से राज्य के बाहर किसी स्थान सहित, स्थानीय क्षेत्र के अन्दर इसको लाते हुए, स्थानीय क्षेत्र में इसके उपभोग, उपयोग या उसमें विक्रय के लिए, माल का प्रवेश कराना या स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र के अन्दर इसका लाया जाना अभिप्रेत है ;

(ख) "किसी स्थानीय क्षेत्र में मोटर यान लाना" से राज्य के बाहर किसी स्थान सहित, स्थानीय क्षेत्र के अन्दर इसको लाते हुए स्थानीय क्षेत्र में इसकी खपत, उपयोग या उसमें विक्रय के लिए, मोटर यान का प्रवेश कराना या स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र के अन्दर इसका लाया जाना अभिप्रेत है;

(ग) “कारबार” के अन्तर्गत है,—

- (i) व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण की प्रकृति का कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, कोई प्रोद्यम या समुत्थान चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान लाभ कमाने हेतु किया जाता है या नहीं और चाहे उससे कोई लाभ प्रोद्भूत होता है या नहीं; और
  - (ii) ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से सम्बन्धित या प्रासंगिक कोई संव्यवहार;
- (घ) “आयुक्त” से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त अभिप्रेत है;
- (ङ) “व्यौहारी” से ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो कारबार के अनुक्रम में, चाहे अपनी ओर से या किसी प्रमुख (प्रिन्सीपल) की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी माल को स्थानीय क्षेत्र में लाता है या परिदान करता है या किसी स्थानीय क्षेत्र में उसके प्रवेश पर माल का परिदान करने का हकदार है, अभिप्रेत है; और इसके अन्तर्गत कोई आकस्मिक व्यौहारी तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खण्ड (छ), के स्पष्टीकरण—I, स्पष्टीकरण—II, स्पष्टीकरण—III सहित, उप-खण्डों (i), (ii), (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट समस्त अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित हैं ;
- (च) “किसी स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश” से राज्य से बाहर के किसी स्थान सहित, किसी बाहर के स्थान से, इसके सभी व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए माल का प्रवेश अभिप्रेत है;
- (छ) किसी व्यौहारी के सन्दर्भ में “सकल आवर्त” से माल के मूल्य की संकलित रकम, जिसे ऐसा व्यौहारी, किसी दी गई अवधि के दौरान

किसी स्थानीय क्षेत्र में इसके उपभोग या उपयोग के लिए लाता है या प्राप्त करता है, अभिप्रेत है;

- (ज) “स्थानीय प्राधिकरण सम्बन्धी विधि” से, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994, छावनी अधिनियम, 2006, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है;
- (झ) “स्थानीय क्षेत्र” से स्थानीय प्राधिकरण की परिसीमाओं में समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ञ) “स्थानीय प्राधिकरण” से स्थानीय प्राधिकरण सम्बन्धी विधि के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ट) स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में “स्थानीय माल” से उस स्थानीय क्षेत्र में प्रविष्ट माल से सुभिन्न (अलग) स्थानीय मूल का माल अभिप्रेत है;
- (ठ) “किसी माल की प्राप्ति” से किसी माल का परिदान या कब्जा लेना, अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल को प्राप्त करवाना, चाहे वह वास्तविक या रचनात्मक है, अभिप्रेत है;
- (ड) “अनुसूची” से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ढ) “राज्य” से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
- (ण) “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (त) “कर” से इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है;
- (थ) “कराधेय आवर्त” से धारा 7 के अधीन यथा अवधारित कर के लिए दायी माल के मूल्य की संकलित रकम, अभिप्रेत है;
- (द) “मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ध) “संकर्म संविदा” से निम्नलिखित संकर्मों हेतु नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए कोई करार अभिप्रेत है:—

(i) किसी भवन, सड़क, पुल या किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति का सन्निर्माण, सुसज्जा, सुधार, रख-रखाव या मरम्मत; या

(ii) किसी जंगम सम्पत्ति का विनिर्माण, प्रसंस्करण, गढ़न (फेब्रिकेशन), परिनिर्माण, संस्थापन, सुसज्जा, सुधार, परिवर्तन, मरम्मत, संपरिवर्तन, कमिशन; और

(न) “वर्ष” से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) उन पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं और हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

(3) इस अधिनियम में “माल का प्रवेश किया गया है” पद के व्याकरणीय रूपभेदों और सजातीय पदों का, चाहे पृथक्कृत: या अन्य शब्दों के संयोजन में प्रयुक्त किया गया हो, के किसी निर्देश के अन्तर्गत, जहां कहीं भी आवश्यक हो “माल के प्रवेश को कारित किया गया” के निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा।

कर का  
भार।

**3. (1)** व्यौहारी के कारबार के दौरान, अनुसूची -2 में विनिर्दिष्ट माल के प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या वहां विक्रय के लिए प्रवेश पर कर को उद्गृहीत और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर, अनुसूची -2 के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर व्यौहारी के कराधेय आवर्त पर संदेय होगा और ऐसा कर, प्रत्येक व्यौहारी द्वारा संदत्त किया जाएगा।

(3) प्रत्येक व्यौहारी, जो एक वर्ष में एक लाख रूपए मूल्य का कोई माल, विनिर्माण में उपयोग या माल के प्रसंस्करण के लिए स्थानीय क्षेत्र में लाता है और प्रत्येक अन्य व्यौहारी, जो एक वर्ष में दो लाख रूपए के मूल्य का कोई माल, स्थानीय क्षेत्र में लाता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के लिए दायी होगा।

(4) उपधारा (1), (2) या (3) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई कर, निम्नलिखित की बाबत उद्गृहीत नहीं किया जाएगा—

- (i) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल ;
- (ii) अनुसूची-2 की क्रम संख्या 6 और 7 पर विनिर्दिष्ट माल के सिवाय, ऐसा माल जिस पर मूल्य परिवर्धित कर संदत्त किया जा चुका हो या राज्य को संदेय हो ;
- (iii) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट ऐसा माल, जिसे स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात्, उसी रूप में राज्य के बाहर या अन्तर्राज्य व्यापार अथवा वाणिज्य या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान, विक्रय किया जाता है; और
- (iv) ऐसा माल जिसके प्रवेश पर निर्धारण प्राधिकारी के समाधान के अनुसार यह साबित हो जाता है कि ऐसे माल पर पहले ही इस अधिनियम के अधीन प्रवेश कर लगाया गया है:

परन्तु यदि कोई व्यौहारी, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल को पुनः विक्रय के प्रयोजन के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करवाता है, जब ऐसे माल का, उसके पुनः विक्रय से भिन्न किसी भी रूप में उपभोग करता है या ऐसे माल का किसी अन्य रीति में व्यवहार करता है, तो वह ऐसे माल की बाबत, कर के संदाय के लिए दायी होगा:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जब कोई व्यौहारी, अपने कारबार के दौरान इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के लिए दायी है, रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति या व्यौहारी से माल का क्रय करता है, जिसने ऐसे माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश ऐसे क्रय से पूर्व किया है, तो कर उस व्यौहारी द्वारा संदत्त किया जाएगा, जिसने ऐसे माल को क्रय किया है।

**स्पष्टीकरण.**—इस धारा के प्रयोजन के लिए संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए, किसी उपभोग या उपयोग के लिए स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश, कारबार के दौरान, माल का प्रवेश समझा जाएगा और वह व्यक्ति, जिसने ऐसे माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश किया है, व्यौहारी समझा जाएगा।

(5) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अनुसूची-1 या अनुसूची-2 में किसी माल को उसमें समाविष्ट या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी या कर की दरों सहित इन अनुसूचियों को अन्यथा संशोधित कर सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूचियां तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएंगी।

मोटर यानों  
पर कर के  
उद्ग्रहण के  
विशेष  
उपबन्ध।

4. (1) इस अधिनियम की धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, उपयोग या विक्रय के लिए किसी मोटर यान के किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, परन्तु ऐसा मोटर यान, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण चिन्ह(मार्क) समुनुदेशित करने के लिए दायी होगा:

परन्तु मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन कृत्यशील कोई भी रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन प्राधिकारी, तब तक ऐसे मोटर यान को रजिस्टर नहीं करेगा, जब तक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति, इस धारा के अधीन निर्धारण प्राधिकारी से संदेय कर को जमा करने का सबूत प्रस्तुत नहीं कर देता:

परन्तु यह और कि उस मोटर यान की बाबत, जो उस तारीख से पूर्व, जिसको यह उस अधिनियम के अधीन राज्य में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, पन्द्रह मास या अधिक अवधि के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन किसी राज्य क्षेत्र या किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत किया गया था, से कोई कर उद्गृहीत और संदत्त नहीं किया जाएगा।

(2) मोटर यान के क्रय मूल्य पर उद्गृहीत कर, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन अधिसूचित मूल्य परिवर्धित कर की दर और मोटर यान के क्रय से सम्बंधित बीजक में यान के विक्रय पर प्रभारित मूल्य परिवर्धित कर या केन्द्रीय विक्रय कर की दर के बीच के अन्तर के बराबर की दर पर होगा:



परन्तु इस धारा के प्रयोजन के लिए राज्य में लागू मूल्य परिवर्धित कर की दर, मोटर यान के क्रय से सम्बन्धित बीजक में वर्णित तारीख से ली जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि मोटर यान के क्रय के सम्बन्ध में कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है या यदि बीजक सम्बद्ध राज्य में लागू, यथास्थिति, मूल्य परिवर्धित कर की दर या केन्द्रीय विक्रय कर नहीं दर्शाता है, तो इस धारा के अधीन उद्गृहीत कर की दर, निर्धारण की तारीख को हिमाचल प्रदेश में लागू मूल्य परिवर्धित कर की दर पर संगणित करके प्रभारित की जाएगी।

**5.** जहां कोई व्यक्ति किसी मोटर यान को, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन किसी संघ राज्य क्षेत्र या किसी अन्य राज्य में इसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पन्द्रह मास की अवधि के भीतर, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में लाता है और ऐसा प्रवेश, राज्य में, ऐसे संघ राज्य क्षेत्र या राज्य से उसके निवास के स्थान के बदलने के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो आयुक्त या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस सम्बन्ध में उसे किए गए आवेदन पर, लिखित में आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को इस सम्बन्ध में, सबूत को प्रस्तुत करने के अध्वधीन, ऐसे यान के प्रवेश पर, प्रवेश कर के संदाय से छूट दे सकेगा।

**6.** धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन व्यौहारी द्वारा या धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर, निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार उद्गृहीत किया जाएगा:—

धारा 3 के अधीन कर उद्गृहीत करने के सिद्धांत।

- (क) कर तब तक देय नहीं होगा, जब तक व्यौहारी या अन्य व्यक्ति, अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करवाता;
- (ख) जब ऐसे किसी माल का, यथास्थिति, किसी व्यौहारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय किया जाता है, तो जब तक उसके द्वारा प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे माल का उस स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए प्रवेश किया गया है; और

- (ग) जब कोई व्यौहारी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल का, स्थानीय क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति या व्यौहारी से क्रय करता है, जो रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी नहीं है, तो जब तक उसके द्वारा प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, यह उपधारणा की जाएगी कि उस द्वारा ऐसे माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश, ऐसे व्यौहारी द्वारा क्रय किए जाने से पूर्व किया गया था।

सकल आवर्त से कटौतियां। **7. (1)** किसी अवधि के लिए कराधेय आवर्त की संगणना करते समय, कोई व्यौहारी, उस अवधि के दौरान, माल के अपने सकल आवर्त में से निम्नलिखित कटौती कर सकेगा, —

- (क) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल का मूल्य;
- (ख) माल का मूल्य, जो उपयोग, उपभोग या विक्रय किए बिना स्थानीय क्षेत्र के बाहर परिदत्त किया गया है;
- (ग) माल का मूल्य, जो चाहे ऐसे रूप में या उसी रूप में इस अधिनियम के अधीन एक बार कर के अध्वधीन कर दिया गया है; और
- (घ) ऐसे अन्य माल का मूल्य, जिस पर विशेष रूप से छूट दी गई है या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन कराधेय नहीं है।

**स्पष्टीकरण.**—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए केवल ऐसे माल के मूल्य की कटौती अनुज्ञेय होगी, जो व्यौहारी के सकल आवर्त का भाग रूप है और यदि कतिपय माल के मूल्य की एक खण्ड के अधीन कटौती की गई है, तब किसी अन्य खण्ड के अधीन इसकी कटौती नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन दावाकृत कटौतियाँ, ऐसे सबूत के, ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुतिकरण के अध्वधीन होंगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए। निर्धारण प्राधिकारी, प्रस्तुत किए गए सबूत की मौलिकता तथा शुद्धता के बारे में अपने समाधान के लिए किसी सुसंगत साक्ष्य की मांग कर सकेगा।

8. जब किसी व्यौहारी या किसी व्यक्ति द्वारा, छावनी बोर्ड की कतिपय परिसीमाओं में समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर, प्रवेश कर देय मामलों में छूट है और छावनी बोर्ड द्वारा उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए माल के उस (सैट-ऑफ)। स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर, प्रवेश कर या चुंगी के रूप में कोई कर उद्गृहीत हो, तो ऐसा व्यौहारी या व्यक्ति, या तो छावनी बोर्ड को उसके द्वारा वास्तव में संदत्त किए गए कर का सबूत या इस अधिनियम के अधीन देय कर के बराबर की रकम, जो भी कम हो, की छूट (सैट-ऑफ) का हकदार होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई छूट(सैट-ऑफ) तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी, जब तक ऐसा व्यौहारी या व्यक्ति, छावनी बोर्ड द्वारा वसूलीय कर या चुंगी संदत्त करने का प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर देता।

9. (1) यह साबित करने का भार व्यौहारी पर होगा, कि —

सबूत का भार।

(क) उसने अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल का उपभोग, उपयोग, या विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है ;

(ख) उसने संकर्म संविदा के निष्पादन में उपभोग या उपयोग के लिए किसी माल का, स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करवाया है;

(ग) वह कराधेय क्रय मूल्य की संगणना के प्रयोजन के लिए स्थानीय माल के मूल्य के सम्बन्ध में कटौती का हकदार है;

(घ) स्थानीय क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति या व्यौहारी से, जो रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी नहीं है, क्रय किया गया माल, उस द्वारा क्रय किए जाने से पूर्व उस स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं हुआ था; और

(ङ) वह कराधेय आवर्त की संगणना में किसी अन्य कटौती का हकदार है।

(2) स्थानीय माल के क्रय मूल्य की बाबत, जिसका उपभोग, उपयोग या विक्रय उसी स्थानीय क्षेत्र में किया गया है, जिसके सम्बन्ध में ऐसा माल स्थानीय

माल है, कटौती के दावे के प्रयोजन के लिए व्यौहारी, धारा 11 की उपधाराओं (1) और (2) में उपबन्धित ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से, जिससे उसने उस स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय माल का क्रय किया है, धारा 11 में विनिर्दिष्ट रीति में अभिप्राप्त बिल, बीजक या नकद पर्ची पेश करेगा ।

रजिस्ट्रीकरण । **10.** प्रत्येक व्यौहारी, जो इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कर संदत्त करने का दायी है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी होगा :

परन्तु यदि ऐसा व्यौहारी, हिमाचल प्रदेश मूल्य कर परिवर्धित अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, तो वह इस अधिनियम के 2005 का 12 अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा ।

रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों द्वारा इस अभिव्यक्ति का बिल इत्यादि जारी किया जाना कि विक्रीत माल स्थानीय माल है ।

**11.** (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी जो, अपने कारबार के दौरान अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी माल का स्थानीय क्षेत्र में ऐसी रीति से विनिर्माण, उत्पादन या पैदावार करता है, कि माल उस स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय माल बन जाता है, ऐसे स्थानीय माल को, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को विक्रय करने पर विनिर्दिष्ट रूप से इस अभिव्यक्ति का बिल, बीजक या नकद पर्ची जारी करेगा, कि विक्रय किया जा रहा माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय माल है और ऐसे माल पर कोई प्रवेश कर संदत्त नहीं किया गया है ।

(2) जब उपधारा (1) में वर्णित माल का, उनके कारबार के दौरान, श्रृंखलाबद्ध के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों द्वारा क्रय या विक्रय किया जाए, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति का विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, बिल या बीजक या नकदी पर्ची जारी करेगा ।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, स्थानीय माल के क्रयों और उपभोग, उपयोग या विक्रय का अलग लेखा रखेगा और उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसके सम्बन्ध में माल स्थानीय माल है, उस द्वारा किए गए स्थानीय माल के विक्रय के लिए अलग बिल पुस्तक और बीजक रखेगा ।

## (4) जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी—

(क) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपने कारबार के दौरान स्थानीय माल का, अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को विक्रय करता है और उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति देने में असफल रहता है; और

(ख) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कारबार के दौरान उस द्वारा क्रय किए गए स्थानीय माल का, अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को विक्रय करता है और उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित बिल, नकद पर्ची या बीजक जारी नहीं करता है ;

तो यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस प्रकार विक्रय किए गए माल पर प्रवेश कर के अपवंचन को सुकर बनाया है और तदानुसार वह ऐसे माल पर देय प्रवेश कर की रकम से डेढ़ गुना के बराबर शास्ति के संदाय के लिए प्रत्येक ऐसे उल्लंघन के लिए दायी होगा, मानों वह स्थानीय मूल का माल नहीं था ।

**12.** इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धाराएं 3, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 63 और 64 तथा उनके अधीन जारी या लागू किए गए नियम, आदेश तथा अधिसूचनाएं, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और देय प्रवेश कर के सम्बन्ध में व्यौहारी पर लागू होंगी, मानों ये धाराएं यथा आवश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम में सम्मिलित की गई थी और इन धाराओं के अधीन लागू किए गए नियम, आदेश और अधिसूचनाएं, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम में इस प्रकार सम्मिलित की गई सुसंगत धाराओं के अधीन जारी किए गए थे।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना।

**13.** इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन, इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी ब्याज या शास्ति सहित, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन, कर का निर्धारण, पुनर्निर्धारण, वसूली करने और कर के संदाय का प्रवर्तन करने के लिए तत्समय सशक्त प्रवेश कर का निर्धारण, वसूली इत्यादि।

प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संदेय किसी ब्याज या शास्ति सहित, कर का निर्धारण, पुनर्निर्धारण, वसूली या कर के संदाय का प्रवर्तन करेगा।

आदेशों की  
अंतिमता।

**14.** इस अधिनियम में अभिव्यक्ततः उपबन्धित के सिवाय, निर्धारण प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, अन्तिम होगा और किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन या कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं होगा और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अधीन की गई या की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में या भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जाने वाली किसी वसूली के सम्बन्ध में, किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा व्यादेश मन्जूर नहीं किया जाएगा।

नियम  
बनाने की  
शक्ति।

**15.** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर के उद्ग्रहण और संग्रहण को सुनिश्चित करने और साधारणतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम से संगत, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर पन्द्रह दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे, जो एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों, या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियमों में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2005 के  
अधिनियम  
संख्यांक  
16 का  
निरसन।

**16.** हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2005 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

**अनुसूची-1**  
(धारा 2 और 3 देखें)

क्रम संख्या	माल	छूट की शर्तें
1.	हस्त परिचालित और पशु द्वारा चलाए जाने वाले कृषि उपकरण ।	—
2.	किसी व्यक्ति द्वारा या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा विक्रीत/जड़ी बूटियों या सैपलिंग्स सहित कृषि या बागवानी उपज जो उसके द्वारा स्वयं उगाई गई हों या ऐसी किसी भूमि पर उगाई गई हो जिसमें उसका कोई हित, चाहे स्वामी या भोग बन्धकदार या अभिधारी के रूप में या अन्यथा हो ।	—
3.	विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए गए साधन और उपकरण ।	—
4.	पशुदाना (ऐनीमल फीड) और दाना परिपूरक अर्थात् मुर्गीदाना, पशुदाना (कैटल फीड), सुअर दाना, मछली दाना, मत्स्य भोजन, प्रॉन फीड, श्रिम्प फीड, और दाना परिपूरक के रूप में विक्रीत प्रसंस्कृत वस्तु के रूप में, घास, सूखी घास और भूसा, दालों के छिलके (भूसी), गेहूँ का चोकर, एडीटिव और डी-आयॅलड केक सहित, दाना परिपूरकों के रूप में प्रयोग के लिए आशयित खनिज मिश्रण सान्द्र ।	—
5.	कृषि प्रयोजनों में प्रयुक्त बांस से निर्मित वस्तुएं ।	—
6.	बान ।	—
7.	सभी प्रकार की चूड़ीयां (मंहगी धातुओं से निर्मित के सिवाय) ।	—
8.	मानचित्र, चार्ट और ग्लोब सहित पुस्तकें, पत्रिकाएं और जरनल्ज ।	—
9.	ब्रेड ।	—
10.	चारकोल ।	—
11.	चरखा, अम्बर चरखा; हथकरघे, हिमाचली हथकरघों से निर्मित वस्तुएं, लोई और पट्टू सहित हिमाचली हथकरघा शालें, टोपियां और हैण्ड स्पन यार्न और गांधी टोपी ।	—
12.	रासायनिक खाद, रासायनिक खाद का मिश्रण, जैविक खादें और माइक्रोन्यूट्रीएन्ट, वनस्पति विनियामक और वनस्पति वृद्धि न्यूट्रीएन्ट ।	—
13.	धान, चावल और गेहूँ से भिन्न मोटा अनाज ।	—

1	2	3
14.	निरोध (कन्डोम) और गर्भनिरोधक ।	—
15.	अट्टियों में कपास सूत और अट्टियों में रेशमी सूत ।	—
16.	दही, लस्सी, बटर मिल्क और सेपरेटिड मिल्क ।	—
17.	मिट्टी के बर्तन (अनग्लेज्ड) ।	—
18.	विद्युत ऊर्जा ।	—
19.	जलाने की लकड़ी ।	जब घरेलू उपयोग के लिए विक्रय की जाए ।
20.	मछली जाल, मछली जाल का धागा और फिश सीडज ।	—
21.	भारत सरकार द्वारा मुफ्त में दिया जाने वाला अनाज, टारगेटड पी.डी. एस.(बी.पी. एल.), अन्तोदय अन्नयोजना और अन्नपूर्णा योजना ।	—
22.	ताजा फल ।	—
23.	ताजा दूध और पासच्यूरान्ड मिल्क ।	—
24.	ताजा पौधे, पौध और ताजा फूल ।	—
25.	ताजी सब्जियां ।	—
26.	लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, आलू, शकरकन्द, टेपिओका और उनके बीज ।	—
27.	केन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा सेना में सेवारत कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों को सीधे विक्रीत माल ।	—
28.	विनिर्माण के पश्चात् या अन्यथा, सीमा शुल्क बॉण्ड के अधीन पुनर्निर्यात के लिए लिया गया माल ।	—
29.	ग्रेफाइट पेन्सिल, लिखने वाले चॉक, लिखने वाली स्लेट और स्लेट पेंसिल, क्रेऑन, स्कैच पैन, ड्राइंग कलर इरेजर, रबर, शार्पनर, फुटरूल, रेखा गणित बॉक्स, स्याही की टिक्की, स्कूलों में प्रयुक्त की जाने वाली अभ्यास और चित्रकला पुस्तकें और विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली तख्तायां ।	—
30.	गुड़ और जैगरि ।	—
31.	हवन सामग्री ।	—
32.	मानव रक्त और रक्त प्लाज्मा ।	—



1	2	3
33.	हाथ से बने हुए स्वदेशी संगीत वाद्य ।	—
34.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विक्रीत मिट्टी का तेल ।	—
35.	खादी के वस्त्र और खादी से निर्मित वस्तुएं ।	—
36.	कृपाण ।	—
37.	कुमकुम, बिन्दी, अल्टा और सिन्दूर ।	—
38.	पत्तल और डूने (जब कम्प्रेसड न हों) ।	—
39.	मांस, मछली, प्रॉन और अन्य जलीय उत्पाद जो संसाधित या फ्रोजन न हो; अण्डे और पशुधन तथा जानवरों के बाल ।	सील्ड डिब्बों में विक्रय किए गए के सिवाय ।
40.	मिश्री, बताशा, फुलियां, मखाना और चिड़वा ।	
41.	राष्ट्रीय ध्वज ।	—
42.	सरकारी खजानों द्वारा विक्रीत नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर; सरकार द्वारा विक्रीत पोस्टल वस्तुएं, जैसे कि लिफाफे, पोस्टकार्ड इत्यादि; रूपए का नोट जब उसे भारतीय रिजर्व बैंक को बेचा जाए और चैक चाहे अबद्ध या पुस्तिका के रूप में हो ।	—
43.	जैविक खाद ।	—
44.	पापड़ ।	—
45.	राखी ।	—
46.	कच्ची ऊन (रॉ वूल) ।	—
47.	नमक ।	—
48.	तेल बीजों के सिवाय सभी प्रकार के बीज ।	—
49.	जमे हुए वीर्य सहित वीर्य ।	—
50.	कॉकून और कच्चा रेशम देने वाला रेशम का कीड़ा ।	—
51.	कच्चा हरा नारियल ।	—
52.	निम्नलिखित के सिवाय— (i) ऐरिएटेड मिनरल, डिसटिल्ड, मेडिसिनल, ऑयोनिन, बैटरी, डी-मिनरलाईज्ड वाटर; और (ii) बन्द डिब्बों में विक्रय किया जाने वाला जल ।	—

**अनुसूची -2**

(धारा 2 और 3 देखें )

क्रम संख्या	माल	कर की दर
1	2	3
1.	डीजल, भट्टी का तेल और चिकनाई (लुब्रिकेन्ट)।	सात प्रतिशत।
2.	विस्फोटक ।	पांच प्रतिशत ।
3.	लोहा और इस्पात ।	चार प्रतिशत ।
4.	सीमेंट ।	पांच प्रतिशत ।
5.	राज्य में प्राइवेट व्यक्तियों सहित सरकारी विभागों/ निगमों/ बोर्डों द्वारा निष्पादित की जा रही हाइड्रोपावर और थर्मल पावर परियोजनाओं के उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं, दूरसंचार और अन्य टर्न की परियोजनाओं के संविदा संकर्मों में प्रयुक्त माल।	पांच प्रतिशत ।
6.	तम्बाकूयुक्त पान मसाला और गुटका।	चार प्रतिशत ।
7.	अनिर्मित तम्बाकू सहित सिगार, चुर्रुट, सिगरेट और तम्बाकू तम्बाकू का कचरा तथा बीड़ी और गुटका सहित अन्य तम्बाकू निर्मित उत्पाद ।	चार प्रतिशत ।

---

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA  
ACT, 2010**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

***Sections:***

1. Short title and extent.
2. Definitions.
3. Incidence of taxation.
4. Special provisions of levy of tax on motor vehicles.
5. Exemption of tax on motor vehicles in certain circumstances.
6. Principles governing levy of tax under section 3.
7. Deductions from gross turnover.
8. Set off in certain cases.
9. Burden of proof.
10. Registration.
11. Registered dealers to issue bill etc. stating that goods sold are local goods.
12. Certain provisions of VAT Act to apply.
13. Assessment, collection etc. of entry tax.
14. Finality of orders.
15. Power to make rules.
16. Repeal of Act No 16 of 2005.

SCHEDULES.

**THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA ACT, 2010**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 7TH APRIL, 2010)

AN

ACT

*to provide for the levy and collection of a Tax on Entry of Goods into Local Area in the State of Himachal Pradesh.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and extent. **1.** (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010.

(2) It shall extend to all the local areas in Himachal Pradesh.

Definitions. **2.** (1) In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

- (a) “bring goods into a local area” means causing the entry of goods into a local area by bringing them inside the local area or causing the goods to be brought inside the local area from any place outside the local area including a place outside the State for consumption, use or sale therein;
- (b) “bring motor vehicle into a local area” means causing the entry of motor vehicle into a local area by bringing it inside the local area or causing it to be brought inside the local area from any place outside the local area including a place outside the State for consumption, use or sale therein;

- 
- (c) “business” includes,—
- (i) any trade, commerce, manufacture, any adventure or concern, in the nature of trade, commerce or manufacture, whether or not; such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make profit and whether or not any profit accrues therefrom; and
  - (ii) any transaction in connection with or ancillary to such trade, commerce, manufacture, adventure or concern;
- (d) “Commissioner” means the Excise and Taxation Commissioner appointed under sub-section (1) of section 3 of the VAT Act;
- (e) “dealer” means any person who, in the course of business, whether on his own account or on account of a principal or any other person, brings or causes to be brought into a local area any goods or takes delivery or is entitled to take delivery of goods on its entry into a local area and includes a casual dealer and all other persons specified in sub-clauses (i), (ii), (iii) and (iv), including Explanation-I, Explanation-II, Explanation-III, of clause (g) of section 2 of the VAT Act;
- (f) “entry of goods into a local area” with all its grammatical variations and cognate expressions means entry of goods into a local area from any place outside thereof including a place outside the State for consumption, use or sale therein;
- (g) “gross turnover” used in relation to any dealer means the aggregate amount of the value of goods which such dealer brings or receives in any local area or consumption or use therein during any given period;
- (h) “law relating to local authority” means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, the Cantonment Act, 2006, the

---

Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, as the case may be;

- (i) “local area” means the area comprised within the limits of a local authority;
- (j) “local authority” means an authority constituted under a law relating to local authority;
- (k) “local goods” in relation to a local area means goods of local origin as distinct from goods which enter into that local area;
- (l) “receives any goods” means to take delivery or possession of any goods, whether actual or constructive, or cause the goods to be received by any other person;
- (m) “Schedule” means a Schedule appended to this Act;
- (n) “State” means the State of Himachal Pradesh;
- (o) “State Government” means Government of Himachal Pradesh;
- (p) “tax” means the tax leviable under this Act;
- (q) “taxable turnover” means the aggregate amount of the value of the goods liable to tax as determined under section 7;
- (r) “VAT Act” means the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005;
- (s) “works contract” means any agreement for—
  - (i) the construction, fitting out, improvement, maintenance or repair of any building, road, bridge or any other immovable property; or
  - (ii) manufacture, processing, fabrication, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair,

conversion or commissioning of any movable property, for cash, deferred payment or other valuable consideration; and

(t) “Year” means the financial year.

(2) All those expressions, which are used but are not defined in this Act and are defined in the VAT Act, 2005, shall have the meanings assigned to them in that Act.

(3) Any reference in this Act to the expression “has effected entry of goods” with its grammatical variations and cognate expressions, whether used in isolation or in conjunction with any other words, shall, wherever necessary, be construed as including a reference to “has caused to be effected entry of goods”.

**3. (1)** There shall be levied and paid to the State Government a tax on the entry, in the course of business of a dealer, of the goods specified in Schedule-II, into each local area for consumption, use or sale therein. Incidence of taxation.

(2) The tax under sub-section (1) shall be payable on the taxable turnover of a dealer at the rates specified in column (3) of Schedule-II and such tax shall be paid by every dealer.

(3) Every dealer who brings any goods into a local area of a value of one lakh rupees in a year, for use in manufacture or processing of goods and every other dealer who brings into a local area any goods of the value of two lakh rupees in a year, shall be liable to pay tax under this Act.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1), (2) or (3), no tax under this section shall be levied—

- (i) in respect of the goods specified in Schedule-I;
- (ii) in respect of the goods on which Value Added Tax has been paid or has become payable to the State, except goods specified at Sr. Nos. 6 and 7 of Schedule-II;

- (iii) in respect of goods specified in Schedule-II, which after entry into a local area are sold in the same form outside the State or in the course of *inter-State* trade or commerce or in the course of export out of the territory of India; and
- (iv) in respect of goods on the entry of which it is proved to the satisfaction of the Assessing Authority that such goods have already been subjected to tax under this Act:

Provided that if any dealer who has effected entry of any goods specified in Schedule-II into a local area for the purpose of re-sale, consumes such goods in any form or deals with such goods in any other manner, except reselling the same, he shall be liable to pay tax in respect of such goods:

Provided further that notwithstanding anything contained in this Act, where a dealer liable to pay tax under this Act in the course of his business, purchases goods from a person or a dealer other than a registered dealer who has effected entry of such goods into the local area prior to such purchase, the tax shall be paid by the dealer who has purchased such goods.

**Explanation.**— For the purpose of this sub-section the entry of goods into a local area for consumption or use therein in the execution of a works contract shall be deemed to be the entry of goods in the course of business and the person who has effected the entry of such goods into a local area shall be deemed to be a dealer.

(5) The State Government may, by notification, add to or delete from the Schedule-I or Schedule-II any goods, or otherwise amend these Schedules, including rates of tax, and thereupon the Schedules shall be deemed to have been amended accordingly.

Special  
provisions  
of levy of  
tax on  
motor  
vehicles.

**4. (1)** Notwithstanding anything contained in section 3 of this Act, there shall be levied and collected a tax on the entry of a motor vehicle by a person into a local area for use or sale therein, provided that such motor vehicle is liable for registration or assignment of a new registration mark in the State under the Motor Vehicles Act, 1988:



Provided that no Registering and Licensing Authority, functioning under the Motor Vehicles Act, 1988, shall register such motor vehicle unless the person making application for registration furnishes proof of having deposited the tax payable under this section from the Assessing Authority:

Provided further that no tax shall be levied and paid in respect of a motor vehicle which was registered in any Union Territory or any other State under the Motor Vehicles Act, 1988, for a period of fifteen months or more before the date on which it is registered in the State under that Act.

(2) The tax shall be levied on purchase value of a motor vehicle at the rate equal to the difference between the rate of value added tax notified under the VAT Act and the rate of value added tax or the central sales tax charged, on the sale of the motor vehicle, in the invoice relating to the purchase of the vehicle:

Provided that for the purpose of this section, the rate of value added tax applicable in the State shall be taken as on the date mentioned in the invoice relating to the purchase of the motor vehicle:

Provided further that if no invoice in respect of purchase of the motor vehicle is produced or if the invoice does not show the rate of the value added tax applicable in the concerned State or the central sales tax, as the case may be, charged, then the rate of tax leviable under this section shall be calculated at the rate of value added tax applicable in Himachal Pradesh on the date of assessment.

**5.** Where any person brings a motor vehicle into a local area for his personal use within a period of fifteen months from the date of its registration in any Union Territory or any other State under the Motor Vehicles Act, 1988, and that such entry is occasioned as a result of shifting the place of his residence from such Union Territory or State into this State, the Commissioner or any other officer duly authorized by him, may, by order in writing, on application made to him in this regard, exempt such person from the payment of entry tax on entry of such vehicle subject to production of proof.

Exemption of tax on motor vehicles in certain circumstances. 59 of 1988.

Principles  
governing  
levy of tax  
under section  
3.

**6.** The tax payable by a dealer under sub-section (1) of section 3 or by any person under sub-section (1) of section 4 shall be levied in accordance with the following principles:-

- (a) tax shall not be payable unless the dealer or other person effects entry of goods specified in the Schedule into a local area;
- (b) where any such goods are consumed, used or sold in a local area by a dealer or as the case may be, by such other person it shall be presumed until the contrary is proved by him, that such goods had entered into that local area for consumption, use or sale therein; and
- (c) when a dealer purchases goods specified in the Schedule in a local area from a person or a dealer who is not a registered dealer, it shall be presumed, unless the contrary is proved by him, that the entry of such goods had been effected by him into such local area before they were purchased by such dealer.

Deductions  
from gross  
turnover.

**7.** (1) In calculating the taxable turnover for any period, a dealer may deduct from his gross turnover of goods during that period, —

- (a) the value of goods specified in Schedule-I;
- (b) the value of goods which, without use, consumption or sale, have been delivered outside the local area;
- (c) the value of goods which have been subjected to tax once as such or in the same form under this Act; and
- (d) the value of such other goods as are specifically exempted or are not taxable under any provision of this Act.

**Explanation.**—For the purpose of this sub-section, deduction of value of only such goods shall be admissible which forms part of gross turnover of the dealer and if value of certain goods has been deducted under one clause then it shall not be deducted under any other clause.

(2) The deductions claimed under sub-section (1) shall be subject to production of such proof in such form and in such manner as the State Government may notify. The Assessing Authority may ask for any relevant evidence to satisfy itself about the genuineness and correctness of the proof furnished.

**8.** Where entry tax is payable by a dealer or by any person in respect of the entry of goods into a local area comprised within the limits of a Cantonment Board and a tax in the nature of a tax or octroi is levied by the Cantonment Board on the entry of goods into that local area for consumption, use or sale therein, such dealer or person shall be entitled to a set off of an amount equal to either the tax proved to have been actually paid by him to the Cantonment Board or the tax payable under this Act, whichever is less:

Set off in certain cases.

Provided that no set off shall be admissible under this section unless such dealer or person furnishes the certified documentary evidence of having paid a tax or octroi recovered by the Cantonment Board.

**9. (1) The burden of proving—**

Burden of proof.

- (a) that a dealer has not effected the entry of any goods specified in the Schedule into a local area for consumption, use or sale therein;
- (b) that a dealer has not effected the entry of any goods into a local area for consumption or use therein in the execution of a works contract;
- (c) that a dealer is entitled to deduction in respect of value of local goods for the purpose of the computation of taxable purchase value;
- (d) that goods purchased by a dealer in a local area from a person or a dealer who is not a registered dealer had not entered into that local area before they were purchased by him; and

- (e) that a dealer is entitled to any other deductions in computing the taxable turnover;

shall be on the dealer.

(2) For purposes of claiming deduction in respect of the purchase value of local goods which have been consumed, used or sold in the same local area in relation to which such goods are local goods, the dealer shall produce a bill, invoice or cash memo in the manner specified in section 11 obtained from the registered dealer from whom he has purchased the local goods in that local area as provided in sub-sections (1) and (2) of section 11.

Registration. **10.** Every dealer who is liable to pay tax under sub-section (1) of section 3 of this Act shall be liable to be registered under this Act:

Provided that if such dealer is registered under the VAT Act, 2005, 12 of 2005 he shall be deemed to have been registered under this Act.

Registered dealers to issue bill etc. stating that goods sold are local goods.

**11.** (1) Every registered dealer who, in the course of his business, manufactures, produces or grows any goods specified in the Schedule in a local area in such manner that the goods become local goods in relation to that local area, shall, on the sale of such local goods to any other registered dealer, issue to him a bill, invoice or cash memo, specifically stating that the goods being sold are local goods in relation to such local area and that no entry tax has been paid on such goods.

(2) Where the goods mentioned in sub-section (1) are purchased and sold in the course of their business by a chain of registered dealers, the selling registered dealer shall issue a bill or invoice or cash memo, containing the statement referred to in sub-section (1).

(3) Every registered dealer referred to in sub-sections (1) and (2) shall maintain a separate account of purchases and consumption, use or sale of local goods and separate bill books and invoices for the sales of goods effected by him in the same local area in relation to which the goods are local goods.

## (4) Where a registered dealer—

- (a) referred to in sub-section (1) or sub-section (2) has, in the course of his business, sold local goods to other registered dealer and has failed to make the statement referred to in sub-section (1), and
- (b) referred to in sub-section (2) in the course of business has sold local goods purchased by him to other registered dealer and a bill, cash memo or invoice has not been issued by him as required by sub-section (2),

it shall be presumed that he has facilitated evasion of tax on the local goods so sold and accordingly he shall be liable for each of such contravention to pay penalty equal to one and a half times the amount of entry tax payable on such goods as if they were not goods of local origin.

**12.** Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the provisions of sections 3, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 63 and 64 of the VAT Act, 2005 and the rules, orders and notifications issued or applicable thereunder, shall *mutatis mutandis* apply to the dealer in respect of tax levied and payable under this Act as if these sections were *mutatis mutandis* incorporated in this Act and the rules, orders and notifications applicable under these sections were *mutatis mutandis* issued under the relevant sections as so incorporated in this Act.

Certain provisions of VAT Act to apply.

12 of 2005

**13.** Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the authorities for the time being empowered under the VAT Act, 2005, to assess, re-assess, collect and enforce payment of tax, including any interest or penalty payable under this Act, shall assess, reassess, collect and enforce payment of tax, including an interest or penalty levied and payable under this Act.

Assessment, collection etc. of entry tax.

**14.** Save as otherwise expressly provided in this Act, every order made by an assessing authority, appellate authority or a revising authority under this Act, shall be final and shall not be called in question in any original

Finality of orders.

suit, application or execution or proceedings and no injunction shall be granted by any court or other authority, in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under the Act or in respect of any recovery to be made as an arrear of Land Revenue.

Power to  
make rules.

**15.** (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules consistent with the Act, for securing the levy and collection of tax and generally for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of fifteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the Assembly agrees in making any modifications in the rules or the Assembly decides that the rule should not be made, such rules shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything done earlier under that rule.

Repeal of  
Act No. 16  
of 2005.

**16.** The Himachal Pradesh Local Area Development Tax Act, 2005 is hereby repealed.

**SCHEDULE- I**  
(See sections 2 and 3)

<b>Sl. No.</b>	<b>Goods</b>	<b>Conditions of exemption</b>
1	2	3
1.	<b>Agricultural implements manually operated or animal driven.</b>	—
2.	Agriculture or horticulture produce, including herbs or saplings of trees sold by person or a member of his family, grown by himself or grown on any land in which he has an interest whether as owner or usufructuary mortgagee, tenant or otherwise.	—
3.	Aids and implements used by handicapped persons.	—
4.	Animal feed and feed supplements, namely, processed commodity sold as poultry feed, cattle feed, pig feed, fish feed, fish meal, prawn feed, shrimp feed and feed supplements and mineral mixture concentrates, intended for use as feed supplements including grass, hay and straw, Husk of Pulses, wheat bran, Additives & Deoiled cakes.	—
5.	Articles made of bamboo-wood used for agricultural purposes.	—
6.	Baan.	—
7.	Bangles of all types (except those made of precious metals).	—
8.	Books, periodicals and journals including maps, charts & Globe.	—
9.	Bread.	—
10.	Charcoal.	—
11.	Charkha, Ambar Charkha; handlooms, Himachali handloom articles, Himachali handloom shawls including 'Loi' & Pattu', caps and handspun yarn, and Gandhi Topi.	—
12.	Chemical fertilizers and chemical fertilizer mixtures; Bio fertilizers & micronutrients, plant regulators and plant growth nutrients.	—
13.	Coarse grains other than paddy, rice and wheat.	—
14.	Condoms and contraceptives.	—
15.	Cotton yarn in hank and silk yarn in hank.	—

1	2	3
16.	Curd, lassi, butter milk and separated milk.	
17.	Earthen wares (unglazed).	—
18.	Electric Energy.	—
19.	Fire wood.	When Sold for domestic use
20.	Fishnet, fish fabrics and fish seeds.	—
21.	Foodgrains supplied free of cost by the Government of India, Targeted P.D.S.(B.P.L.), Antodya Anna Yojna & Annapurna Yojna.	—
22.	Fresh fruits.	—
23.	Fresh milk and pasteurised milk.	—
24.	Fresh plants, sapling and fresh flowers.	—
25.	Fresh vegetables.	—
26.	Garlic, ginger, green chillies, onions, potatoes, sweet potatoes, tapioca and their seeds.	—
27.	Goods sold to the serving military personnel and ex-servicemen by the Canteen Store Department direct.	—
28.	Goods taken under customs bond for re-export after manufacturing or otherwise.	—
29.	Graphite pencils, writing chalk, Writing Slate & Slate Pencils, crayons, sketch, pens, drawing colour eraser, sharpener, footrules, geometry boxes, ink tablets, exercise and drawing books of the type used in schools and takhties used by students.	—
30.	Gur & Jaggery.	—
31.	Hawan Samagri.	—
32.	Human blood and blood plasma.	—
33.	Indigenous handmade musical instruments.	—
34.	Kerosene oil sold through Public Distribution System.	—
35.	Khadi Garments & madeups.	—
36.	Kirpan.	—
37.	Kumkum, bindi, alta and sindur.	—



1	2	3
38.	Leaf plates and leaf-cups (when not compressed).	—
39.	Meat, fish, prawn and other aquatic products when not cured or frozen; eggs and live stock and animal hair.	Except when sold in sealed containers
40.	Misri, Patasha, Fullian, Makhana and Chirbara.	—
41.	National flag.	—
42.	Non-Judicial stamp paper sold by Government Treasuries; postal items like envelope, postcard etc. sold by Government; rupee note when sold to the Reserve Bank of India and cheques, loose or in book form.	—
43.	Organic manure.	—
44.	Papad.	—
45.	Rakhi.	—
46.	Raw wool.	—
47.	Salt.	—
48.	Seeds of all kinds except oil seeds	—
49.	Semen including frozen semen.	—
50.	Silk worm laying cocoon and raw silk.	—
51.	Tender green coconut.	—
52.	Water other than— (i) aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, demineralised water, and (ii) water sold in sealed container.	

**SCHEDULE-II****[See sections 2 and 3]**

<b>Sr.No.</b>	<b>Goods</b>	<b>Rate of tax</b>
1.	Diesel, furnace oil and lubricants.	7%
2.	Explosives.	5%
3.	Iron and Steel.	4%
4.	Cement.	5%
5.	Goods used in works contracts, including hydropower and thermal power projects generation, transmission and distributions projects, telecommunications and all other turnkey projects being executed by private as well as Govt. Deptt./Corporations/Board etc. in the State.	5%
6.	Pan Masala and gutka containing tobacco.	4%
7.	Cigars, Cheroots, Cigarettes including un-manufactured tobacco and tobacco, tobacco refuse and other manufactured tobacco products, including bidies and gudaka.	4%

**Election Urgent**  
**Time Bound**



**राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश**

**STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH**

आर्म्सडेल, शिमला-171002, Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152

No.SEC.13-85/2006-I-918-27

Dated the 8th April, 2010

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers vested in it under section 19 and 281 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and rule 22 and 69 of the Himachal Municipal (Election) Rules, 1994, the State Election Commission Himachal Pradesh hereby notifies the election programme for the conduct of bye-election to fill up the vacant seat of ward No. 4 Nagar Panchayat Rewalsar of District Mandi Himachal Pradesh as under:-

1. Nomination papers to be filed : On 16<sup>th</sup>, 17<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> April, 2010 (between 11.00 am to 3.00 pm) Nomination papers shall be filed at the place, and before the officer appointed by the Returning Officer (Deputy Commissioner).
2. Scrutiny of nomination papers : On 20<sup>th</sup> April, 2010.
3. Withdrawal of candidature : On 22<sup>nd</sup> April, 2010 (before 3.00 pm)
4. The list of contesting candidates : On 22<sup>nd</sup> April, 2010 immediately after the time of withdrawal is over. The list of contesting candidates will indicate the name of symbol allotted to them.
5. Polling Stations : The list of polling stations shall be made public and pasted on or before 16<sup>th</sup> April, 2010.
6. Date of Poll, if necessary : On 8<sup>th</sup> May, 2010 between 7.00 am to 3.00 pm
7. Counting of votes, in the event of poll : On 8<sup>th</sup> May, 2010 immediately after the polling is over at Nagar Panchayat Headquarter
8. Declaration of election result : On 8<sup>th</sup> May, 2010 immediately after the counting is over.

**Note:** The election process shall be completed by 12<sup>th</sup> May, 2010.

**By Order**  
**(Dev Swarup)**  
**State Election Commissioner**  
**Himachal Pradesh.**

---

**हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय****अधिसूचना**

शिमला-4, 5 अप्रैल, 2010

**संख्या वि०स०-लैज-गवननमेंट बिल/1-14/2010.**—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-3) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,  
**गोवर्धन सिंह,**  
सचिव, हि० प्र० विधान सभा।

## हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 21) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**1.** इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

**2.** हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 1 में,— धारा 1 का संशोधन।

(क) "संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ" शीर्षक के स्थान पर "संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना" शीर्षक रखा जाएगा; और

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (3) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3) यह ऐसे क्षेत्र को लागू होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अभिहित करे।”।

**3.** मूल अधिनियम की धारा 2 में, विद्यमान खण्डों (क), (ख), (च), (छ) और (द) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :— धारा 2 का संशोधन।

“(क) “विज्ञापन” से किसी प्लॉट, रिहायशी भवन या अपार्टमेंट या वाणिज्यिक प्लॉट/भवन की बिक्री, पट्टे पर देने या अनुमोदन

(मंजूरी) की प्रस्थापना करने या ऐसे किसी प्लॉट, रिहायशी भवन या अपार्टमेंट या वाणिज्यिक प्लॉट/भवन को लेने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करने या ऐसे प्रयोजनों के लिए अग्रिम देने अथवा निक्षेप करने के लिए जनसाधारण को किया गया दृश्यरूपण अभिप्रेत है चाहे वह घोषणा या प्रदर्शन के माध्यम से हो या किसी अन्य रीति में हो ;

- (ख) किसी रिहायशी भवन, अपार्टमेंट, परिसर, फ्लैट या प्लॉट के सम्बन्ध में "आबंटिती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सम्प्रवर्तक द्वारा ऐसे रिहायशी भवन या अपार्टमेंट या परिसर या फ्लैट या प्लॉट का आबंटन किया गया है, विक्रय किया गया है या किराए पर, पट्टे पर, अनुज्ञप्ति पर दिया गया हो या अन्यथा अन्तरित किया गया हो ;
- (च) "संगम" से अपार्टमेंट के बहुसंख्यक स्वामियों, रिहायशी भवन या कालोनी के अधिभोगियों से गठित कोई संगम अभिप्रेत है जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार समूह के रूप में कार्य कर रहा है ;
- (छ) "भवन" से किसी भूमि पर निर्मित भवन, जिसमें पांच या अधिक अपार्टमेंट हों या दो या अधिक भवन हों जिनमें कुल पांच या अधिक अपार्टमेंट हों, या कोई विद्यमान भवन, जिसे पांच या अधिक अपार्टमेंटों में सम्परिवर्तित किया गया है, अभिप्रेत है ;
- (द) "आन्तरिक विकास संकर्म" से सड़कें, पैदल चलने के रास्ते, जल आपूर्ति, मलनालियां, नालियां, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली, वृक्षारोपण, स्ट्रीट लाइटिंग, सामुदायिक भवनों के लिए तथा मल और मैले पानी के अभिक्रियान्वयन के लिए व्यवस्था या कालोनी में इसके उचित विकास के लिए आवश्यक कोई अन्य संकर्म अभिप्रेत है;" ।

धारा 4 का  
संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) में "पांच हजार" और "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "पांच लाख" और "दस लाख" शब्द रखे जाएंगे।

## 5. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

धारा 5 का  
संशोधन।

- (क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,  
अर्थात्:—

“(3) जहां उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आदेश पारित कर दिया गया है वहां सक्षम प्राधिकारी, संप्रवर्तक द्वारा, प्रति बीघा या उसके भाग के लिए पांच लाख रुपए की दर से, बैंक ड्राफ्ट के रूप में विकास प्रभार जमा करवाने के पश्चात् तथा संप्रवर्तक द्वारा विहित प्ररूप में इस प्रकार प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार विकास कार्यों (सकंमों) के पूर्ण करने को कार्यान्वित करने के लिए करार करके वचनबद्ध होने पर, विहित प्ररूप में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा:

परन्तु संप्रवर्तक इस उपधारा के अधीन जमा किए गए बैंक ड्राफ्ट पर किसी ब्याज का हकदार नहीं होगा।”।

- (ख) उपधारा (8) में “चालीस बीघा या अधिक है” और “पांच प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “पांच बीघा या अधिक है या जहां तीस से अधिक फ्लैटों का निर्माण किया जाना है” और “दस प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे; और

- (ग) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,  
अर्थात्,—

“(9) संप्रवर्तक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए समस्त निदेशों की, अभिन्यास के निष्पादन की सम्यक् अनुपालना और उस पर विकास कार्यों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा ऐसे निष्पादन का निरीक्षण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अनुज्ञप्त करने के लिए, पालना करेगा :

परन्तु संप्रवर्तक, भवनों या अपार्टमेंटों का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व, अनिवार्य संरचना अर्थात् सड़कों, फुटपाथों, जल-आपूर्ति तथा मलवहन की पूर्णरूपेण व्यवस्था करेगा।”।

- (घ) उपधारा (12) में “बैंक गारंटी या प्रतिभूति के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप” शब्दों के स्थान पर “बैंक ड्राफ्ट के रूप में” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 14 का  
संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 14 में विद्यमान उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

- “(3) यदि सम्प्रवर्तक धारा 6 के अधीन यथा अपेक्षित विक्रय के लिखित करार को निष्पादित करने में असफल रहता है, या उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट, अपार्टमेंट या प्लॉट के हस्तान्तरण विलेख और अन्य सुसंगत दस्तावेजों का निष्पादन तीन मास के भीतर करने में असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी, या तो शिकायत (परिवाद) पर या स्वप्रेरणा से प्लॉट या अपार्टमेंट जिसके लिए व्यतिक्रम हुआ है, प्लॉट या अपार्टमेंट की कीमत के अधिकतम पांच प्रतिशत तक या पचास हजार रुपए तक, जो भी अधिकतर हो, शास्ति और प्रत्येक प्लॉट या अपार्टमेंट हेतु, प्रत्येक दिन, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, के लिए पांच सौ रुपए की अतिरिक्त न्यूनतम शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, और ऐसी शास्ति धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन निक्षिप्त बैंक ड्राफ्ट के विरुद्ध वसूल की जा सकेगी :

परन्तु यदि शास्ति की बैंक ड्राफ्ट के विरुद्ध पूर्णतया वसूली नहीं की जाती है, तो अतिशेष की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

धारा 15 का  
संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) में “पांच हजार” शब्दों के स्थान पर “पचास हजार” शब्द रखे जाएंगे।



8. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा धारा 21 का प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—  
प्रस्थापना ।

“21. धारा 19 के अधीन जारी सम्प्रवर्तक और सम्पदा अभिकर्ता का प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात्, इसे इस निमित्त सम्प्रवर्तक और सम्पदा अभिकर्ता द्वारा विहित फीस के साथ किए गए आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दो वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा:

परन्तु धारा 20 में निर्दिष्ट शर्तें पूर्ण की जाती रहें और आवेदन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व किया गया हो।” ।

9. मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित धारा 24 का परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
संशोधन ।

“परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति प्रक्रिया स्तर पर अपने आवेदन को प्रत्याहृत करने का आशय रखता है, तो वह ऐसी फीस के पचहत्तर प्रतिशत के प्रतिदाय का हकदार होगा।” ।

10. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में “दस रुपए” धारा 30 का शब्दों के स्थान पर “सौ रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।  
संशोधन ।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 21) स्वामित्व के आधार पर अपार्टमेंटों के निर्माण, विक्रय, अन्तरण और प्रबन्धन के उन्नयन को विनियमित करने, कालोनियों तथा सम्पत्ति संव्यवहारों को विनियमित करने, तथा सम्प्रवर्तकों तथा सम्पदा अभिकर्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबन्ध करने तथा सम्प्रवर्तकों और सम्पदा अभिकर्ताओं पर बाध्यताओं का प्रवर्तन करने और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करता है। यह देखा गया है कि सम्प्रवर्तक, राज्य के विभिन्न स्थानों पर बेतरतीब (अव्यवस्थित) तरीके से निर्माण कर रहे हैं। सम्प्रवर्तकों द्वारा किए जा रहे बेतरतीब निर्माण को नियंत्रित करने (रोकथाम करने) के लिए यह प्रस्तावित किया गया है कि कतिपय क्षेत्रों को अभिहित किया जाना चाहिए जहां पर सम्प्रवर्तकों को निर्माण करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके ताकि राज्य की पारिस्थितिकी को संरक्षित रखा जा सके। विद्यमान उपबन्ध के अनुसार सम्प्रवर्तकों द्वारा, विकास प्रभारों के पच्चीस प्रतिशत के लेखे (शोधनार्थ), बैंक गारण्टी या डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रतिभूति जमा करना अपेक्षित है जो सम्प्रवर्तक को प्रतिदेय है। इस प्रतिभूति के हिमुडा के हित में बेहतर उपयोग हेतु यह प्रस्तावित किया गया है कि बैंक गारण्टी के बजाए सम्प्रवर्तकों को उक्त प्रतिभूति बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तावित किया गया है कि विकास प्रभार प्रति बीघा या उसके भाग के लिए पांच लाख रुपए की दर से प्रभारित किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अधिनियम के उपबन्धों को और प्रभावी और कठोर बनाने के लिए अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए जुर्माने की मात्रा में वृद्धि करना प्रस्तावित किया गया है। इसलिए, हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन अधिनियम, 2005 का यथोचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(महेन्द्र सिंह),  
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख: ..... 2010

### वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं और इससे राजकोष पर कोई अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं होगा।

### प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

— शून्य —

**Bill No. 3 of 2010**

**THE HIMACHAL PRADESH APARTMENT AND PROPERTY  
REGULATION (AMENDMENT) BILL, 2010**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

**BILL**

*further to amend the Himachal Pradesh Apartment and Property  
Regulation Act, 2005 ( Act No. 21 of 2005).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in  
the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

**1.** This Act may be called the Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation (Amendment) Act, 2010. Short title.

**2.** In section 1 of the Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation Act, 2005 (hereinafter referred to as the ‘principal Act’),— Amendment of section 1.

(a) for the heading “Short title and commencement”, the heading “Short title, commencement and application” shall be substituted; and

(b) after sub-section (2), the following sub-section (3) shall be inserted, namely:—

“(3) It shall apply to such area as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, designate.”.

Amendment  
of section 2.

**3.** In section 2 of the principal Act, for the existing clauses (a), (b), (f), (g) and (r), the following clauses shall respectively be substituted, namely:—

- “(a) “advertisement” means visible representation made to the general public either through announcement or display or in any other manner whatsoever, offering for sale, lease or approval of a plot, residential building or apartment or commercial plot/building or inviting persons to take such plot, residential building or apartment or commercial plot/building or to make advances or deposits for such purposes ;
- (b) “allottee” in relation to a residential building, apartment, premises, flat or plot, means the person to whom such residential building or apartment or premises or flat or plot has been allotted, sold or given on rent, lease, license or otherwise transferred by the promoter ;
- (f) “association” means an association consisting of majority of the apartment owners, occupants in a residential building or colony acting as a group in accordance with the provisions of this Act or any other law for the time being in force;
- (g) “building” means a building constructed on any land, containing five or more apartments, or two or more buildings with a total of five or more apartments, or any existing building converted into five or more apartments;
- (r) “internal development works” mean roads, foot-paths, water supply, sewers, drains, rain water harvesting system, tree planting, street lighting, provision for community buildings and for treatment and disposal of sewage and sullage water, or any other work in a colony necessary for its proper development ;”.

**4.** In section 4 of the principal Act, in sub-section (5), for the words “five thousand” and “fifty thousand”, the words “five lacs” and “ten lacs” shall respectively be substituted. Amendment of section 4.

**5.** In section 5 of the principal Act,— Amendment of section 5.

(a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(3) Where an order is passed granting permission under sub-section(2), the competent authority shall grant a license in the prescribed form, after the promoter has deposited development charges at the rate of five lacs rupees per bigha or part thereof in the shape of bank draft and the promoter has undertaken to enter into an agreement in the prescribed form for carrying out completion of development works in accordance with the conditions of the license so granted:

Provided that the promoter shall not be entitled to any interest on the bank draft deposited under this sub-section.”.

(b) in sub-section (8), for the words “forty bighas or more” and “five per cent”, the words “ five bighas or more or where more than 30 flats are to be constructed” and “ten per cent” shall respectively be substituted;

(c) for sub-section (9), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(9) The promoter shall carry out all directions issued by the competent authority for ensuring due compliance of the execution of the lay out and the development works therein and to permit the competent authority or any officer authorised by it to inspect such execution :

Provided that before commencement of construction of building or apartments, the promoter shall fully provide essential infrastructure i.e. roads, foot-paths, water supply and sewerage.”; and

- (d) in sub-section (12), for the words “as a result of enforcement of bank guarantee or security”, the words “bank draft” shall be substituted.

Amendment  
of section  
14.

- 6.** In section 14 of the principal Act, for existing sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(3) If the promoter fails to execute a written agreement of sale as required under section 6, or fails to execute the conveyance deed of apartments or plots and other relevant documents as specified in sub-section (1), within three months, the competent authority may, either on a complaint or suo moto, impose for each plot or apartment for which there is a default, a penalty upto a maximum of five percent of the price of the plot or the apartment or fifty thousand rupees, whichever is greater, and further minimum penalty of five hundred rupees for each day for which the default continues for each plot or apartment, and such penalty may be recovered against the bank draft deposited under sub-section (3) of section 5 :

Provided that the penalty if not recovered fully against the bank draft, the balance shall be recovered as arrear of land revenue.

Amendment  
of section  
15.

- 7.** In section 15 of the principal Act, in sub-section (6), for the words “five thousand”, the words “fifty thousand” shall be substituted.

Substitution  
of section  
21.

- 8.** For section 21 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

“Every certificate of registration of a promoter or an estate agent, issued under section 19 shall be valid for a period of two years and on the expiry of such a period, it may be renewed for another period of two years by the competent authority, on an application, alongwith the prescribed fee, made by the promoter or the estate agent in that behalf :

Provided that the conditions referred to in section 20 continue to be fulfilled and the application has been made at least three months before the expiry of the certificate of registration.”.

**9.** In section 24 of the principal Act, after sub-section (4), the following proviso shall be inserted, namely:— Amendment  
of section  
24.

“Provided that if such person intends to withdraw his application at the processing stage, he shall be entitled to the refund of seventy five percent of such fee.”.

**10.** In section 30 of the principal Act, in sub-section (1), for the words “rupees ten”, the words “hundred rupees” shall be substituted. Amendment  
of section  
30.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

---

The Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation Act, 2005 (Act No.21 of 2005) provides to regulate the promotion of the constructions, sale, transfer and management of apartments on ownership basis, to regulate colonies and property transactions and also provide for registration of promoters and estate agents and enforcement of obligations on promoters and estate agents and for matters connected therewith or incidental thereto. It has been observed that the promoters are raising construction in a haphazard manner at various places of the State. To check the haphazard construction being raised by the promoters, it has been proposed that certain areas should be designated where the promoters may be allowed to raise constructions so that ecology of the State may be protected. As per existing provision, the promoters are required to furnish the security by way of bank guarantee or by demand draft on account of 25% of development charges, which is refundable to the promoter. In order to make best use of this security in the interest of HIMUDA, it has been proposed that instead of bank guarantee, the promoters should deposit the said security by way of bank draft. Further, it has also been proposed that the development charges may be charged at the rate of rupees five lacs per bigha or part thereof. Further, in order to make the provisions of the Act ibid more effective and stringent, it has been proposed to increase the quantum of fine for contravention of the provisions of the Act. As such, it has been decided to suitably amend the Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation Act, 2005.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MAHENDER SINGH)  
MINISTER-IN-CHARGE.

SHIMLA :

The \_\_\_\_\_ 2010.



---

### **FINANCIAL MEMORANDUM**

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and there shall be no additional expenditure from the State ex-chequer.

### **MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

—NIL—

---

**PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-9, 31st March, 2010*

**No. PCH-HB(1)24/06-Cab-mem-50708-51082.**—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the following amendment in the provision of the Scheme, notified vide notification No. PCH-HB(1)24/2006-JE-Appt-II- 922-1276 dated 10-4-2008 for engaging Junior Engineers namely;

1. In Sr. No. 4 under heading “**Distribution of Marks**” in order to make out merit of the candidates appeared before the selection committee the maximum marks would be 100 to be distributed in the following manner:-

<b>(A) Education Qualification</b>	
Percentage of marks in degree divided by 1.923 or Percentage of marks in 3 years diploma divided by 2.222	to the maximum of 52 marks.
<b>(B) Experience</b>  Three marks shall be awarded for every one year of experience in relevant nature of duties in any Development Block or in Panchayati Raj institutions.	to the maximum of 20 marks.
<b>(C) Personal Interview</b>	to the maximum of 15 marks.
(D) In case of candidate belongs to the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes or Below Poverty line.	5 Marks
(E) In case candidate is physically handicapped	3 Marks
(F) In case candidate belongs to a family having no member in the employment of Government.	5 Marks

By order,  
Sd/-  
Secretary.